

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 31 मार्च, 1981/10 चैत्र, 1903

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 31 मार्च, 1981

संख्या 1-9/81-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1972 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 (1981 का विधेयक संख्यांक 12) जो कि दिनांक

31-3-81 को हिमाचल प्रदेश चतुर्थ विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया है की एक एक प्रति हिन्दी एवं अंग्रेजी में, सर्व साधारण की सूचनार्थ हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित की जाती है।

राजकुमार महाजन  
सचिव।

1981 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981

(जैसा कि विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1981-82 के कुछ भाग के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियां चुकाने और उनका विनियोग करने हेतु

विधेयक ।

यह भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1981 संक्षिप्त नाम । कहलाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट धन राशियां, जिनका जोड़ छब्बीस करोड़ पैंतालीस लाख उन्तीस हजार एक सौ रुपये (रुपए 26,45,29,100) है निकाली जाए और वित्तीय वर्ष 1981-82 के पहले एक मास की अवधि में अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में निर्दिष्ट प्रभारों को चुकता करने हेतु, उपयोग किया जाए ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वर्ष 1981-82 के लिए 26,45,29,100 रुपए की राशि निकालना ।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम द्वारा जिन धन राशियों को निकालने और उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है उन धनराशियों का विनियोग, धारा 2 में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में प्रदर्शित प्रयोजनों और सेवाओं के लिए किया जाएगा ।

विनियोग ।

**अनुसूची**  
(देखिए धाराएं 2 और 3)

1	2	3		
मांग संख्या	सेवाएँ तथा प्रयोजन	(निम्नलिखित राशियों से अनधिक)		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
1	विधान सभा तथा निर्वाचन राजस्व	8,20,000	9,100	8,29,100
2	राज्यपाल तथा मन्त्रि परिषद् राजस्व	2,22,500	9,400	2,31,900
3	न्याय प्रशासन राजस्व	7,83,500	1,93,500	9,77,000
4	सामान्य प्रशासन राजस्व	40,30,400	77,500	41,07,900
5	भू-राजस्व राजस्व	28,47,200	—	28,47,200
	पूँजी	1,04,500	—	1,04,500
6	आबकारी तथा कराधान राजस्व	11,72,900	—	11,72,900
7	पुलिस तथा अग्नि सुरक्षा राजस्व	72,80,500	—	72,80,500
8	शिक्षा, कला तथा संस्कृति एवं वैज्ञानिक अनुसंधान राजस्व	3,33,79,000	—	3,33,79,000
	पूँजी	4,07,500	—	4,07,500
9	चिकित्सा तथा परिवार कल्याण राजस्व	1,06,86,000	—	1,06,86,000
	पूँजी	25,14,600	—	25,14,600
10	लोक निर्माण राजस्व	2,46,03,000	—	2,46,03,000
	पूँजी	12,85,000	—	12,85,000
11	कृषि राजस्व	81,01,800	—	81,01,800
	पूँजी	21,68,700	—	21,68,700
12	लघु सिंचाई राजस्व	87,10,400	—	87,10,400
	पूँजी	14,66,600	—	14,66,600
13	भूमि तथा जल-संरक्षण राजस्व	33,87,500	—	33,87,500
	पूँजी	4,20,000	—	4,20,000
14	पशु पालन तथा दुग्ध विकास राजस्व	39,31,500	—	39,31,500
	पूँजी	13,66,600	—	13,66,600
15	मत्स्य राजस्व	2,37,500	—	2,37,500
	पूँजी	70,000	—	70,000
16	वन राजस्व	82,25,000	—	82,25,000
	पूँजी	3,58,300	—	3,58,300
17	सड़कें तथा पुल राजस्व	54,80,900	—	54,80,900
	पूँजी	1,57,59,500	—	1,57,59,500
18	आपूर्ति, उद्योग तथा खनिज राजस्व	33,70,600	—	33,70,600
	पूँजी	11,16,600	—	11,16,600

1	2	3		
		रुपये	रुपये	रुपये
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण तथा जेल	राजस्व पूँजी	32,44,700 ---	32,44,700 7,69,000
20	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	राजस्व पूँजी	1,80,74,600 ---	1,80,74,600 31,84,100
21	सामुदायिक विकास	राजस्व पूँजी	78,02,900 ---	78,02,900 2,700
22	सहकारिता	राजस्व पूँजी	18,55,900 ---	18,55,900 17,18,700
23	खाद्य एवं पोषाहार	राजस्व पूँजी	25,11,200 ---	25,11,200 73,62,500
24	जल तथा विद्युत विकास	राजस्व पूँजी	7,91,600 ---	7,91,600 1,21,91,600
25	सिंचाई नावचालन, जल निकास तथा बाढ़ नियन्त्रण	राजस्व पूँजी	6,79,100 ---	6,79,100 10,79,100
26	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	राजस्व पूँजी	12,75,000 ---	12,75,000 1,66,000
27	सड़क परिवहन	राजस्व पूँजी	1,27,000 ---	1,27,000 12,33,300
28	पर्यटन	राजस्व पूँजी	1,27,100 ---	1,27,100 6,55,800
29	श्रम तथा रोजगार	राजस्व पूँजी	10,15,500 ---	10,15,500 8,000
30	आवास	राजस्व पूँजी	3,53,500 ---	3,53,500 13,10,400
31	नगर विकास	राजस्व पूँजी	6,12,500 ---	6,12,500 30,000
32	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	राजस्व पूँजी	26,73,700 ---	26,73,700 72,000
33	वित्त	राजस्व पूँजी	36,25,100 ---	95,43,700 85,08,000
34	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूँजी	14,45,800	14,45,800
35	जन-जातीय विकास	राजस्व पूँजी	1,33,37,900 ---	1,33,37,900 25,43,500
	जोड़	24,61,87,900	1,83,41,200	26,45,29,100

## उद्देश्य तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 1981-82 के पहले एक मास के लिए अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित तथा विधान सभा द्वारा दत्तमत व्यय, पूरा करने के लिए वांछित धन को हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से विनियोग करने की व्यवस्था करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 व 204 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पूरा न होने तक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 की धारा (1) व अनुच्छेद 206 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। मांगी गई राशि में वर्ष 1981-82 में रखी गई नई स्कीमों के प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया है।

राम लाल,  
मुख्य मन्त्री ।

शिमला:  
मार्च 31, 1981.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिस्ताव

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-1-सी (1) 8/80]

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1981 के विषय की सूचना मिलने पर उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरः स्थापित करने तथा उस पर सभा के विचार हेतु अभिस्ताव किया है।

Authorised English text of the Himachal Pradesh Viniyog (Lekhanudan) Vidhaik, 1981 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.

Bill No. 12 of 1981.

**THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1981**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

**BILL**

*to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services of a part of the financial year, 1981-82.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Thirty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 1981.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Twenty-six crores, forty-five lakhs, twenty-nine thousand and one hundred rupees towards defraying several charges which will come in course of payment during the first one month of the financial year, 1981-82 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Withdrawal of Rs. 26,45,29,100 from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1981-82.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period mentioned in section 2 of the Act.

Appropriation.

**THE SCHEDULE**  
(See sections 2 and 3)

1 No. of Vote	2 Services and Purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha and Elections Revenue	8,20,000	9,100	8,29,100
2	Governor and Council of Ministers. Revenue	2,22,500	9,400	2,31,900
3	Administration of Justice Revenue	7,83,500	1,93,500	9,77,000
4	General Administration Revenue	40,30,400	77,500	41,07,900
5	Land Revenue Revenue	28,47,200	—	28,47,200
	Capital	1,04,500	—	1,04,500
6	Excise and Taxation Revenue	11,72,900	—	11,72,900
7	Police and Fire Protection Revenue	72,80,500	—	72,80,500
8	Education, Art and Cultural Revenue	3,33,79,000	—	3,33,79,000
	Affairs and Scientific Research. Capital	4,07,500	—	4,07,500
9	Medical and Family Planning. Revenue	1,06,86,000	—	1,06,86,000
	Capital	25,14,600	—	25,14,600
10	Public Works Revenue	2,46,03,000	—	2,46,03,000
	Capital	12,85,000	—	12,85,000
11	Agriculture Revenue	81,01,800	—	81,01,800
	Capital	21,68,700	—	21,68,700
12	Minor Irrigation Revenue	87,10,400	—	87,10,400
	Capital	14,66,600	—	14,66,600
13	Soil and Water Conservation. Revenue	33,87,500	—	33,87,500
	Capital	4,20,000	—	4,20,000
14	Animal Husbandry and Dairy Development. Revenue	39,31,500	—	39,31,500
	Capital	13,66,600	—	13,66,600
15	Fisheries Revenue	2,37,500	—	2,37,500
	Capital	70,000	—	70,000
16	Forests Revenue	82,25,000	—	82,25,000
	Capital	3,58,300	—	3,58,300
17	Roads and Bridges Revenue	54,80,900	—	54,80,900
	Capital	1,57,59,500	—	1,57,59,500
18	Supplies, Industries and Minerals. Revenue	33,70,600	—	33,70,600
	Capital	11,16,600	—	11,16,600
19	Social Security, Welfare and Jails. Revenue	32,44,700	—	32,44,700
	Capital	7,69,000	—	7,69,000
20	Public Health, Sanitation and Water Supply. Revenue	1,80,74,600	—	1,80,74,600
	Capital	31,84,100	—	31,84,100



1	2	3	Rs.	Rs.	Rs.
21	Community Development	Revenue	78,02,900	—	78,02,900
		Capital	2,700	—	2,700
22	Co-operation	Revenue	18,55,900	—	18,55,900
		Capital	17,18,700	—	17,18,700
23	Food and Nutrition	Revenue	25,11,200	—	25,11,200
		Capital	73,62,500	—	73,62,500
24	Water and Power Development.	Revenue	7,91,600	—	7,91,600
		Capital	1,21,91,600	—	1,21,91,600
25	Irrigation, Navigation, Drainage, and Flood Control.	Revenue	6,79,100	—	6,79,100
		Capital	10,79,100	—	10,79,100
26	Stationery and Printing	Revenue	12,75,000	—	12,75,000
		Capital	1,66,000	—	1,66,000
27	Road Transport	Revenue	1,27,000	—	1,27,000
		Capital	12,33,300	—	12,33,300
28	Tourism	Revenue	1,27,100	—	1,27,100
		Capital	6,55,800	—	6,55,800
29	Labour and Employment	Revenue	10,15,500	—	10,15,500
		Capital	8,000	—	8,000
30	Housing	Revenue	3,53,500	—	3,53,500
		Capital	13,10,400	—	13,10,400
31	Urban Development	Revenue	6,12,500	—	6,12,500
		Capital	30,000	—	30,000
32	Other Administrative Services.	Revenue	26,73,700	—	26,73,700
		Capital	72,000	—	72,000
33	Finance	Revenue	36,25,100	95,43,700	1,31,68,800
		Capital	—	85,08,000	85,08,000
34	Loans to Government Servants.	Capital	14,45,800	—	14,45,800
35	Tribal Development	Revenue	1,33,37,900	—	1,33,37,900
		Capital	25,43,500	—	25,43,500
	Total	..	24,61,87,900	1,83,41,200	26,45,29,100

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 206 of the Constitution of India to provide for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly equal to 1/12th of the estimated expenditure of Government of Himachal Pradesh for the financial year 1981-82 pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 and 204 of the Constitution of India. The moneys demanded do not include the provision for the Really New Schemes included in the Budget for the year 1981-82.

SIMLA :  
The 31st March, 1981.

RAM LAL,  
*Chief Minister.*

---

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE  
CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. 1. C(1)8/80]

The Governor, Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the proposed Himachal Pradesh Appropriation (Vote on Account) Bill, 1981 recommends under Article 207 of the Constitution of India the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.